

y?k ,o dVhj m|kx dk vkfFkd&Ikekftd thou ij iHkko

¼jhok fty d fo'k" k lnHk e½

Mk- jkt'k frokjh

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र

शारदा महाविद्यालय सरला नगर, मैहर (म.प्र.)

y{eh flg dky

शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

'kk/k I kjk'k %&

लघु उद्योग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये उद्योग न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि स्थानीय संसाधनों का आवेकतानुसार उपयोग करके स्थानीय विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। यह उपक्रम आर्थिक उन्नति में आम आदमी की सहभागिता निरूपण के लिए समय-सापेक्ष योजनाओं को तैयार करने में सहायक हाती हैं। छोटे-छोटे निर्माण कार्य लघु उद्योग की आधार भूमि तैयार करते हैं। लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका आकार और उत्पादन क्षमता छोटी होती है। ये उद्योग सामान्यतः स्थानीय स्तर पर संचालित होते हैं और इनमें निवेश और कार्यबल की आवश्यकता कम होती है। लघु उद्योग का मुख्य उद्देश्य छोटे पैमाने पर उत्पादन करना और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना होता है। लघु उद्योग न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करते हैं और स्थानीय बाजारों में उनकी बिक्री करते हैं। इसके अलावा, लघु उद्योग नवाचार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करते हैं।

'kcn cht %&लघु, कुटीर, उद्योग, आर्थिक, सामाजिक, जीवन, सांस्कृतिक सहभागिता, हस्तशिल्प, विकासोन्मुख आदि।

iLrkouk %&

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थान प्राचीनकाल से ही महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यतया वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प-कला, स्वर्ण अलंकार तथा हीरे-जवाहरात के अलंकार, हाथी दांत का काम इत्यादि उद्योगों के संदर्भ में भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। इसकी उन्नति की स्थिति ब्रिटिश शासन काल तक चलती रही, किन्तु ब्रिटिशों ने जो नीति अपनायी उससे भारतीय कुटीर उद्योगों का हास होना शुरू हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति तक उनकी अवनति होने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण बना रहा है तथा योजनाकाल में भी इन उद्योगों को काफी महत्व दिया गया है।

लघु एवं कुटीर उद्योग एक विकासोन्मुख देश की प्रगति में भारी योगदान देते हैं। इन उद्योगों को संतुलित आर्थिक विकास का चिन्ह कहा जा सकता है। वृहद उद्योगों का उद्देश्य लाभ कमाना और उनका आधार स्वयं मनुष्य है न केवल कम विकसित देशों में वरन् विकसित देशों में भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।



सामान्यतः उद्योग तीन प्रकार के होते हैं— वृहद, लघु एवं कुटीर। जो उद्योग बड़ी-बड़ी मशीनों तथा विद्युत-शक्ति की सहायता से चलाये जाते हैं एवं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वे 'वृहद' उद्योग की श्रेणी में आते हैं। "लघु उद्योग" वे हैं जिनमें 'वृहद' उद्योगों की अपेक्षा कम मात्रा में भूमि, पूँजी एवं साहस का उपयोग, होता है। "आर्थिक एवं औद्योगिक जाँच समिति" के अनुसार, "लघु उद्योगों से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से था जिनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक न हो और जिनकी लागत 30 हजार रुपयों तक हो।"। परन्तु आधुनिक संशोधित परिवेश एवं परिस्थिति के अनुसार, "लघु उद्योगों की मुख्य कसौटी यह है कि ऐसे उद्योग जिसमें 7.5 लाख रुपये तक पूँजी लगी हो, उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं है।"

कुटीर उद्योग से आशय उन उद्योग धन्धों से है जिनका संगठन एक स्वतंत्र कारीगर अपनी पूँजी तथा श्रम के साधारण यंत्रों द्वारा करता है। ये उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों द्वारा चलाये जाते हैं और उनमें सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होती। 'भारतीय औद्योगिक नियामक आयोग' ने ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग बताया है जिन्हें श्रमिक अपने घरों में चलाते हैं और जिनके कार्य का आकार छोटा तथा स्थानीय मांग पूरा करने के लिए होता है। लघु तथा कुटीर उद्योग गांवों में भी चलाये जाते हैं और शहरों में भी। जब ये गांव में स्थापित होते हैं तब इन्हें ग्रामीण उद्योग कहते हैं और शहरों में स्थापित होने वाले उद्योगों को शहरी उद्योग कहते हैं।

विकसित तथा विकासोन्मुख दोनों ही प्रकार के देशों में लघु उद्योगों का बड़ा ही महत्व है। एक विकसित देश में इनका महत्व इसके स्थानीयकरण, विधियन एवं विपणन प्रभावों के कारण होता है। विकेन्द्रित कच्चे पदार्थों का विधियन करने वाले कारखाने, (जैसे— डेयरी उद्योग) स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करने वाले और भारी यातायात व्यय का सामान बनाने वाले कारखाने एवं सेवा उद्योग संगठित किये जाते हैं। पृथक योग्य निर्माण कार्य जैसे— मरम्मत, हस्तकला और कलात्मक उत्पादन के उद्योग अपने विधियन प्रभावों के कारण तथा पसन्दगी से प्रभावित उत्पादों जैसे— महिलाओं एवं बच्चों के रेडीमेड आरमेंट्स तथा सीमित बाजार वाले उत्पादों के उद्योग अपने विपणन प्रभावों के कारण लघु उद्योग के रूप में ही स्थापित किये जाते हैं। कुटीर उद्योगों का महत्व मुख्यतः कृषकों को सहायक आय प्रदान करने तथा देश की परम्परागत कला की रक्षा करने की दृष्टि से बताया जाता है। इसके अलावा अनेक और भी तर्क हैं जिनके आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्व स्पष्ट होता है।

लघु उद्यमों की सहायता से पूँजी, उद्यमशीलता, प्रबन्ध कुशलता, श्रम आदि जो साधन बिखरे रहते हैं, उन्हें संजोकर आसानी से काम में लाया जा सकता है। चूँकि बड़े कारखानों के प्रबन्ध के लिए कुशल व्यक्ति आसानी से नहीं मिल पाते तथा कुशल मजदूर नहीं होते, वहाँ लघु उद्योग ही उत्तम सिद्ध होते हैं। साधारणतया लघु उद्योगपति अपने पास से या अपने सम्बन्धियों या अपने मित्रों की सहायता से छोटे कारखाने के लिए पूँजी जुटाने हैं। इस प्रकार लघु उद्योगपति अच्छे प्रबंधक और संगठनकर्ता सिद्ध हो सकते हैं, बाद में यही छोटे उद्योग धीरे-धीरे मझोले तथा बड़े उद्योगों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार बिखरी हुई पूँजी उत्पादन कार्य में आ जाती है। नगरों तथा कस्बों में छोटे कारखाने खोलने से उन सब साधनों का उपयोग हो सकता है जो बहुधा नहीं हो पाता। कच्चे माल की प्राप्ति स्थानों के निकट ही खोले जाने वाले छोटे उद्योगों के कारण उन लोगों को रोजगार मिल सकेगा जो बेकार हैं तथा जिनके पास पूरे समय काम नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों का विकास, स्थान-स्थान पर उद्योग के प्रसार और देहातों से भी उनके विकास का कार्य लघु उद्योगों द्वारा ही हो सकता है। इससे घनी आबादी वाले शहरों में ही केन्द्रित न रहकर अन्य क्षेत्रों में फैल जाते हैं। जिन क्षेत्रों में यातायात तथा संचार सुविधाएँ पर्याप्त न होने से माल बिक्री के लिए छोटे कारखाने ही सबसे अधिक उपयुक्त रहते हैं। वहीं पर कई बड़े उद्योग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें भारी लागत लगाने पर भी बाद में वे असफल सिद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार पूँजी की हानि हो जाती है। छोटे



कारखाने खोलने से यह खतरा नहीं रहता और धन्धा ठीक न होने पर पूँजी को दूसरे उपयुक्त धन्धों में लगाया जा सकता है। छोटे उद्योगों के विकास से स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है और गैर सरकारी उद्योगों में एकाधिकार स्थापित नहीं होता। साथ ही छोटे कारखानों से देश में मध्यम वर्ग के स्वतंत्र उद्योगपतियों का एक ऐसा वर्ग बनेगा जो देश के स्वस्थ सामाजिक विकास में बहुत सहायक होगा।

इस प्रकार अत्यन्त अनुकूल पूँजी-उत्पाद-अनुपात तथा उच्च रोजगार सम्भावनाएँ लघु एवं कुटीर उद्योगों की ऐसी विशेषताएँ हैं जो इनकी उपयोगिता एवं महत्ता में चार चाँद लगा देती हैं। इनमें अपेक्षाकृत कम पूँजी का विनियोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही अधिकाधिक संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करके आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करने में भी सहायक है तथा आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के द्वारा प्रादेशिक असन्तुलनों को भी कम करते हैं। ये ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने माल का लाभ प्रदान करके अपनी रूचि के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने में सहयोग देते हैं। परन्तु स्थानीय विकास के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिन सिद्धान्तों का निर्माण भारतीय जनमानस के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए किया था, उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं हुआ जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका। महात्मा गांधी ने भारत की जनसंख्या का एक तिहाई जनमानस जो कि आज भी गांव में बसता है, उसके आर्थिक विकास का विचार दिया था।

ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण जनता के सहयोग से आर्थिक नीतियां बनाने के लिए प्रचुर सुझाव दिए, लेकिन इन सुझावों-नीतियों को क्रियान्वित करने में चूक हुई है। ग्रामीणों के आर्थिक विकास का सबसे सशक्त माध्यम पशुपालन खेती, लघु कुटीर उद्योग सहित कृषि से सम्बन्धित मुद्दे रहें। तत्कालीन समय में इन सब से बढ़कर खादी उद्योग रहा है। वर्तमान में खादी की वास्तविक स्थिति से रुबरु होंगे, तो कड़वी सच्चाई यह है कि कुल कपड़े के उत्पाद का एक प्रतिशत भी खादी नहीं है जबकि पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से इसे लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

देश के आजाद होने के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं प्रसार के लिए अनेक प्रकार के सरकारी उपाय किये गये हैं। इन उद्योगों के लिये सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में उद्योगों को वित्तीय सुविधाएँ, तकनीकी सुविधाएँ, विपणन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं जिसके फलस्वरूप अब भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अब लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को भविष्य में और विकास करने की आवश्यकता है जिससे कृषि पर लोगों की निर्भरता कम कर उन्हें उद्योग-धन्धों में लगाकर प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाई जा सकती है तथा बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

उत्पादन और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में लघु व कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। कुटीर उद्योग परम्परागत उद्योग हैं, इनमें कम पूँजी लगती है तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तुएं बना ली जाती हैं। लघु उद्योग में भी कम पूँजी लगती है। लघु उद्योग इकाई ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो, किन्तु कुछ मद जैसे कि- हौजरी, हस्त-औजार, दवाइयों व औषधि, लेखन सामग्री मदें और खेलकूद का सामान आदि में निवेश की सीमा 5 करोड़ रु. तक थी, लघु उद्योग श्रेणी को नया नाम लघु उद्यम दिया गया है। सरकार अब इन उद्योगों हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।



आजादी के बाद लघु उद्योगों के विकास के लिये अत्यधिक प्रयास किए गए। सन 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इनके विकास हेतु 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। फिर 1951ए 1977-1980 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियों की घोषणाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया है। सबके मिले जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति हुई तथा इससे देश में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी मदद मिली है।

पंजीकृत तथा कार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना पहली बार 1972 में पूर्ण हुई थी जिसमें 1.40 लाख इकाइयों की गणना की गई थी। वर्तमान गणना 15 वर्ष बाद 1988 में संपन्न हुई है जिसके अनुसार देश में 5.82 लाख इकाइयां कार्यरत हैं। 15 वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्पादन, रोजगार व अन्य दृष्टि से लघु औद्योगिक क्षेत्र ने उच्च वृद्धि दर प्राप्त की है। इनसे वर्ष 1972-73 में 16.53 लाख लोगों को रोजगार मिला था वह वर्ष 1987-88 में बढ़कर 36.66 लाख तक पहुँच गया। निर्यात में भी वृद्धि की दर अधिक रही है। वर्ष 1972-73 में 127 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था जो वर्ष 1987.88 में बढ़कर 2ए499 करोड़ रुपये हो गया। रोजगार एवं निर्यात की सम्भावना को देखते हुए सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिये आवंटन में सातवीं योजना के मुकाबले में आठवीं योजना में चौगुनी वृद्धि की है।

श्रम-प्रधान एवं पूँजी के अभाव से ग्रस्त देश की आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में छोटे उद्योगों का जाल बिछाने की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया है। यह प्रयास गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने के लिये किया गया एक सराहनीय कदम है। 1990-95 तक की अवधि के लिये तैयार इस योजना दस्तावेज में छोटे उद्योगों की तीन उपश्रेणियों में विभाजित करके उनके लिये अलग-अलग रणनीति अपनाने की बात कही गई है, खासकर ऐसे उद्योगों के लिये आधुनिकीकरण कोष स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है और इसके लिये 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की योजना है। इससे 4.5 लाख उद्यमियों के लाभान्वित होने तथा 41.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

सामान्यतया लघु उद्योग में वे व्यवसाय आते हैं जो सीमित, संसाधनों, पूँजी और कर्मचारियों के साथ संचालित होते हैं। इसमें हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, वस्त्र निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, चमड़ा उत्पाद, खिलौने बनाना, और बेकरी जैसे छोटे पैमाने के उद्योग शामिल हैं। ये उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और रोजगार सृजन में योगदान देते हैं। लघु उद्योग कम निवेश में शुरू किए जा सकते हैं और उद्यमियों के लिए लाभदायक अवसर प्रदान करते हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले का विवरण इस प्रकार है –

gLrf'kYi& हाथ से बनाए गए उत्पाद, जिनमें कला और कौशल का उपयोग होता है। लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, कपड़े की कढ़ाई।

[kk] çILdj.k& खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण और पैकेजिंग। मसाले, आटा मिल, अचार, पापड़, जूस।

VDIVkby vkj cukb कपड़े का उत्पादन और बुनाई का कार्य। हस्तनिर्मित साड़ियाँ, कालीन, कंबल।

ydMh dk dke & लकड़ी के फर्नीचर और अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण। कुर्सी, मेज, अलमारी, खिलौने।

धातु शिल्प- धातु से बने सजावटी और उपयोगी उत्पाद। पीतल की मूर्तियाँ, लोहे के ग्रिल, एल्युमिनियम के बर्तन।

—f" k vkëkkfjr m|kx— कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और उनका उपयोग करके उत्पाद बनाना। गुड़ निर्माण, तेल निकालने का कार्य, जैविक खाद निर्माण।

peMk m|kx चमड़े के उत्पादों का निर्माण। जूते, बेल्ट, बैग।

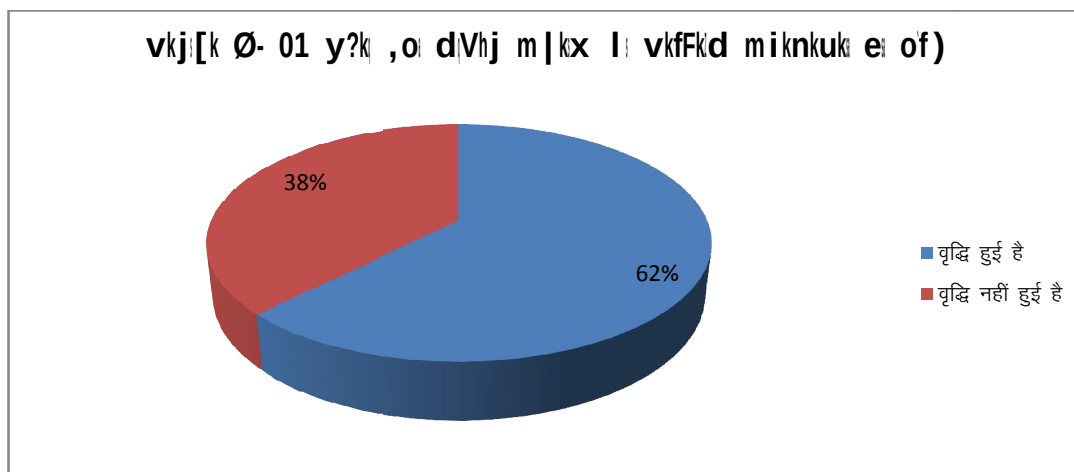


lykfLVd mRikn प्लास्टिक सामग्री का निर्माण— घरेलू सामान, बोतल, प्लास्टिक के बर्तन।
 dlxt vkj LV'kujh कागज और उससे जुड़े उत्पादों का निर्माण। नोटबुक, लिफाफे, फाइल।
 nfud mi; kx dh oLr, रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं, जिनकी स्थानीय स्तर पर खपत होती है। साबुन, मोमबत्ती, अगरबत्ती।
 QkekL; fVdYI छोटी दवा कंपनियां जो सीमित मात्रा में दवाइयों का निर्माण करती हैं। हर्बल उत्पाद, क्रीम, सिरप।
 byDV, fud midj. k छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और उनके पुर्जों का निर्माण। एलईडी लाइट्स, मोबाइल चार्जर।
 tfod mRikn पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का निर्माण। जैविक साबुन, हर्बल शैंपू, जैविक खाद।
 fcfVx vkj idftx उत्पादों की पैकेजिंग और प्रिंटिंग सेवाएं— गत्ते के डिब्बे, प्रिंटेड पाउच।
 ltkoVh lkeku सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान— दीवार की पेंटिंग, शोपीस।
 [ky lkekh खेलों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण— क्रिकेट बैट, फुटबॉल, बैडमिंटन रैकेट।

अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में रीवा जिले के विभिन्न छः विकासखण्डों 20-20 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। रीवा जिला औद्योगिक और कुटीर उद्योग धंधा के लिए नयी कार्य योजनाओं के साथ संकल्पित है। यह जिला पूर्व में राजकीय गतिविधियों का केन्द्र रहा है जिस कारण यहाँ के कुटीर उद्योग धन्धे पारम्परिक हैं। इन कुटीर उद्योग धन्धों में समय के साथ परिमार्जन हो रहा है जिस कारण नयी आर्थिक व्यवस्थाएँ उन्नत हो रही हैं। इस संदर्भ के यथार्थ जानकारी के लिए अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाता से प्राप्त जानकारी का विवेचन निम्न है—

lkj.kh Øekd 01-y?k ,o dVhj m|kx l vkfFkd miknkuk e of

Øekd	fooj.k	l ;k	ifr'kr
1.	वृद्धि हुई है	75	62.5
2.	वृद्धि नहीं हुई है	45	37.5
	;kx	120	100-0



लघु एवं कुटीर उद्योग से आर्थिक उपादानों में वृद्धि के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक स्रोतों की जानकारी से अवगत होता है कि क्रमशः 75(62.5 प्रतिशत) वृद्धि हुई है जबकि 45(37.5 प्रतिशत) वृद्धि नहीं हुई है।

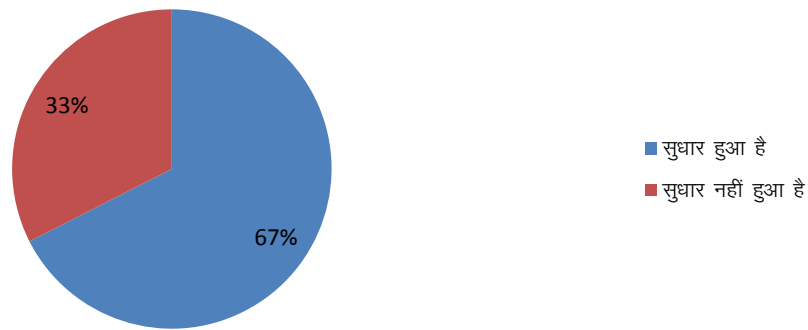
इस प्रकार सारणी के विवरण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 75(62.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लघु एवं कुटीर उद्योग से आर्थिक

उत्पादनों में वृद्धि हुई है की बात स्वीकारते हैं।

I kj.kh Øekd 02-y?k ,o dVhj m|kx I: foUkh; 0;oLFkk e: I/kkj

Øekd	fooj.k	I[;k	ifr'kr
1.	सुधार हुआ है	81	67.5
2.	सुधार नहीं हुआ है	39	32.5
	;kx	120	100-0

vkj[k Ø- 02 y?k ,o dVhj m|kx I: foUkh; 0;oLFkk e: I/kkj



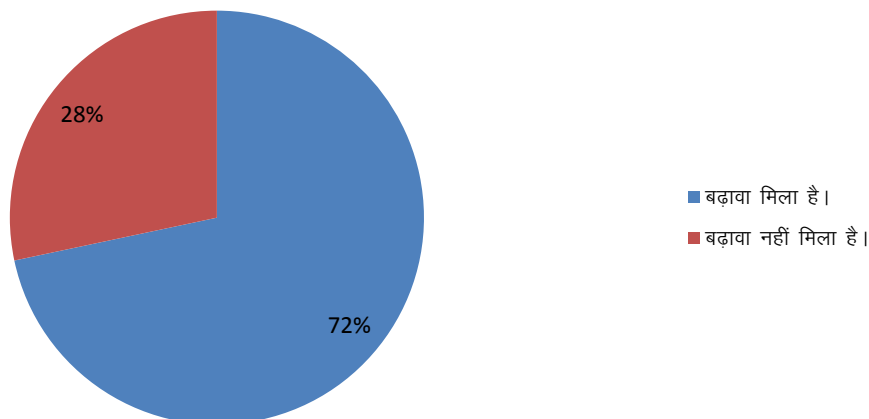
लघु एवं कुटीर उद्योग से वित्तीय व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक स्रोतों की जानकारी से अवगत होता है कि क्रमशः 81(67.5 प्रतिशत) सुधार हुआ है जबकि 39(32.5 प्रतिशत) सुधार नहीं हुआ है। इस प्रकार सारणी के विवरण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 81(67.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लघु एवं कुटीर उद्योग से वित्तीय व्यवस्था में सुधार हुआ है की बात स्वीकार योग्य है।

I kj.kh Øekd&03- foUkh; I LFkkvk I: y?k dVhj m|kx d fodk I dk c<kok

Øekd	fooj.k	I[;k	ifr'kr
1.	बढ़ावा मिला है।	86	71.66
2.	बढ़ावा नहीं मिला है।	34	28.34
	;kx	120	100-00



वर्ष 2023 में; 15 फरवरी को यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार

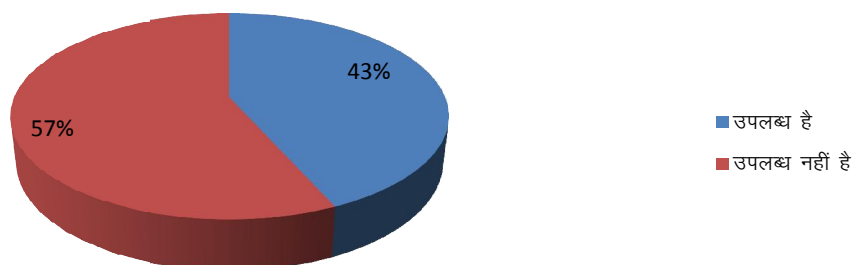


वित्तीय संस्थाओं से लघु कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक स्रोतों की जानकारी से अवगत होता है कि क्रमशः 86(71.66 प्रतिशत) बढ़ावा मिला है जबकि 34(28.34 प्रतिशत) बढ़ावा नहीं मिला है। इस प्रकार सारणी के विवरण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 86(71.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने वित्तीय संस्थाओं से लघु कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है की बात स्वीकार योग्य है।

15 फरवरी को, यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार

वर्ण	वर्ण	संख्या	प्रतिशत
1.	उपलब्ध है	52	43.33
2.	उपलब्ध नहीं है	68	56.67
	कुल	120	100-00

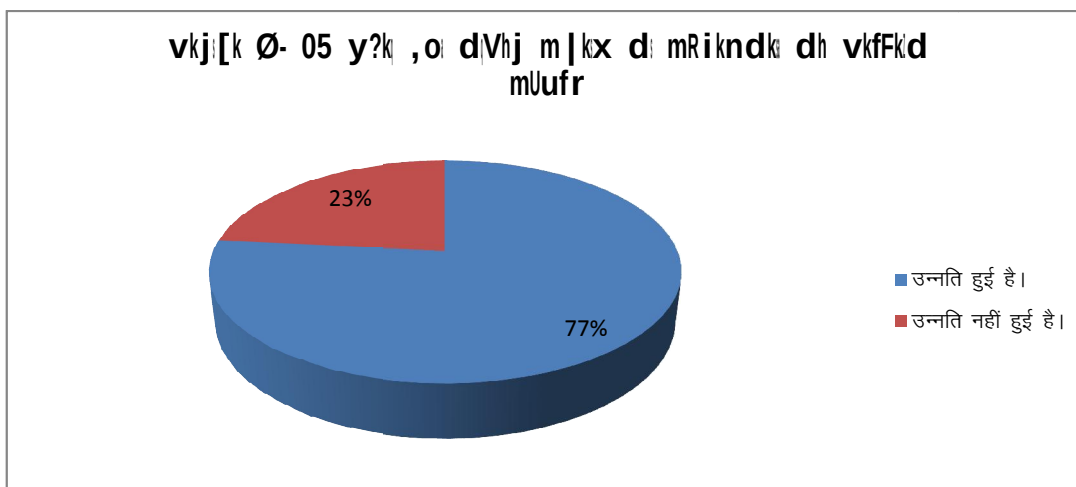
वर्ष 2024 में, यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार



लघु एवं कुटीर उद्योग संचालन के लिए आसान ऋण उपलब्धता के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक स्रोतों की जानकारी से अवगत होता है कि क्रमशः 52(43.33 प्रतिशत) उपलब्ध है जबकि 68(56.67 प्रतिशत) उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार सारणी के विवरण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 68(56.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लघु एवं कुटीर उद्योग संचालन के लिए आसान ऋण उपलब्धता नहीं है की बात स्वीकार योग्य है।

l kj.kh Øekd&05- y?k ,o dVhj m|kx d: mRikndk dh vkfFkd mUufr

Øekd	fooj.k	l; ;k	ifr'kr
1.	उन्नति हुई है।	92	76.66
2.	उन्नति नहीं हुई है।	28	23.34
	;kx	120	100-00



लघु एवं कुटीर उद्योग के उत्पादकों की आर्थिक उन्नति से ग्रामीण उत्पादकों में सुधार के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक स्रोतों की जानकारी से अवगत होता है कि क्रमशः 92 (76.66 प्रतिशत) उन्नति हुई है जबकि 28(23.34 प्रतिशत) उन्नति नहीं हुई है।

इस प्रकार सारणी के विवरण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 92 (76.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लघु एवं कुटीर उद्योग के उत्पादकों की आर्थिक उन्नति से ग्रामीण उत्पादकों में सुधार में उन्नति हुई है की बात स्वीकार योग्य है।

वर्णित लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन और विपणन के विविध संदर्भों में अध्ययन के लिए म.प्र. के विकासशील जिला रीवा में संचालित लघु एवं कुटीर उद्योगों के विभिन्न इकाइयों का चयन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समय के साथ रीवा जिले में पारम्परिक और नवीन लघु एवं कुटीर उद्योग विकसित हो रहे हैं। इन नवीन उपक्रमों में उपभोक्ताओं के जीवनोपयोगी, अवसर अनुसार मांग के अनुकूल वस्तुओं का निर्माण कर विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जाने लगा है। इस प्रयोगधर्मिता ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त किया।

fu"d"kl&

लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक और सामाजिक जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, बल्कि समाज की सामाजिक संरचना को भी मजबूत बनाते हैं। हालांकि, इन उद्योगों को प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहायता और बेहतर मार्केटिंग सुविधाओं की आवश्यकता होती है ताकि वे और अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकें।

इन उद्योगों ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके बेरोजगारी को कम किया है तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में योगदान दिया है। पारंपरिक हस्तशिल्प, बुनाई, मृदभांड (मिट्टी के बर्तन), अगरबत्ती निर्माण, बढ़ईगिरी, और डेयरी जैसे उद्योगों ने न केवल स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग किया है बल्कि आत्मनिर्भरता की भावना को भी बढ़ावा दिया है।

आर्थिक दृष्टि से इन उद्योगों ने स्थानीय बाजारों में पूंजी के प्रवाह को बढ़ाया, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। सामाजिक स्तर पर इनसे सामाजिक एकता, पारिवारिक स्थिरता, और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार जैसे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि “लघु एवं कुटीर उद्योग रीवा जिले के सर्वांगीण विकास की रीढ़ हैं”, जो स्थानीय जनता के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

I|>ko %&

लघु एवं कुटीर उद्योग का आर्थिक-सामाजिक जीवन पर प्रभाव के संदर्भ में किये गये अध्ययन से कुछ ऐसे तथ्य रेखांकित हुए हैं जिनपर समय सापेक्ष नवाचार का प्रयोग करते हुए योजनाओं को संचालित किया जाय तो निश्चय ही छोटे पूंजी के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर सुधार किया जा सकता है। उपरोक्त अध्ययन में पाया गया है कि कुछ तथ्यों पर ध्यानाकर्षित कर उद्यमिता एवं स्वरोजगार नीति का निर्धारण किया जाना उचित होगा इस संदर्भ में चिन्हित विचार बिन्दु सुझाव के रूप में निम्नांकित हैं—

- लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ये उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देते हैं।
- कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। यह ग्रामीण लोगों को बाहर से काम के लिए न भागने का अवसर प्रदान करता है।
- लघु उद्योग स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। यह अन्य उद्योगों की तुलना में सस्ता और आसान होता है, जिससे स्थानीय स्तर पर समृद्धि आती है।
- कुटीर उद्योगों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार को विभिन्न प्रकार के टैक्स और शुल्क मिलते हैं, जो सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोगी होते हैं।
- ये उद्योग उन संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हैं जो अन्यथा बर्बाद हो सकते थे। जैसे कृषि उत्पादों से बने सामान, कच्चे माल का अधिकतम उपयोग।
- लघु उद्योगों के द्वारा श्रमिकों को उचित वेतन और काम के अवसर मिलते हैं, जिससे सामाजिक समृद्धि बढ़ती है। इन उद्योगों में महिलाओं और युवाओं को भी रोजगार मिलने के मौके होते हैं, जिससे समाज में समानता बढ़ती है।



- कुटीर उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आत्मविश्वास में भी सुधार होता है।
- इन उद्योगों में पारंपरिक शिल्प और कौशल को बनाए रखा जाता है, जिससे संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है। इससे स्थानीय कला और शिल्प को भी बढ़ावा मिलता है।
- कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होता है जैसे सड़कें, बिजली, पानी आदि। इससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आता है।
- लघु उद्योगों के बढ़ते प्रभाव से समाज में नयापन आता है और पारंपरिक वर्गीय भेदभाव को भी कम करने में मदद मिलती है। यह छोटे व्यापारियों, शिल्पकारों और अन्य श्रमिकों को अपने कार्यों में पहचान और सम्मान प्रदान करता है।
- लघु उद्योगों में अक्सर नई तकनीक और उपकरणों की कमी होती है, जिससे उत्पादकता कम हो सकती है।
- कुटीर उद्योगों के पास पूंजी की कमी हो सकती है, और वे बड़ी वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।
- इन उद्योगों के उत्पादों का बाजार बहुत अस्थिर होता है, और कभी-कभी कीमतों में गिरावट और मांग में कमी आने से नुकसान होता है।

1. नमूने के लिए सूची

1	गंगेले, डॉ० अरुण,	उद्यमिता विकास	म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी	2008
2	सिंह, सी.डी. एवं वर्मा, आर.डी.	भारत की आर्थिक समस्याएँ	बिहार, हिन्दी ग्रंथ अकादमी	2008
3	धींगरा, ईश्वर	भारतीय अर्थव्यवस्था	एस. चंद्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली	2010
4	चौहान, जीतन सिंह	रीवा राज्य दर्पण	रीवा दरबार से प्रकाशित	2003
5	पंत, जे.सी. एण्ड जैन, एस.सी.	अर्थशास्त्र	साहित्य भवन पब्लिकेशन	2005
6	हैन, डॉ० एम.के.	शोध विधियाँ	यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली	2006
7	शुक्ला, एम.बी.	उद्यमिता	वर्धन पब्लिकेशन	2007
8	महेश्वरी, डॉ० पी.डी.	अर्थशास्त्र	कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल	2009
9	पाटनी, आर.एल.	औद्योगिक अर्थशास्त्र	गोयल पब्लिकेशन आगरा	2008
10	शर्मा, राजेन्द्र	व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत तथा उद्यमिता	कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल	2009
11	सचदेवा, डॉ० सुरेश	व्यवसाय अध्ययन	म.प्र., पाठ्य पुस्तक निगम	2009

